

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-02

देहरादून : दिनांक 13 अगस्त, 2008

विषय:- समाज कल्याण के अधीन संचालित विकलांग, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन एवं विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में धनराशि वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : 162/XVII-02/2008-01(33)/2006 दिनांक 23 जुलाई, 2008 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विभाग की उपरोक्त योजनाओं में धनराशि का भुगतान लाभार्थियों तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त शासनादेश के पैरा-3.2 में यह उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के अन्तर्गत प्रथम किश्त के उपरान्त इन योजनाओं में धनराशि का वितरण डाकघर के माध्यम से ही किया जायेगा।

2. उक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में लाभार्थियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि केवल डाकघरों में ही उक्त योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि वितरण हेतु खाता खोलने की व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है और इसे लाभार्थियों के सुविधा के आधार पर लाभार्थी को विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना उचित होगा।

3. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को उनकी सुविधा के आधार पर पोस्ट आफिस अथवा समस्त कामर्शियल बैंक/ग्रामीण बैंक/को-ऑपरेटिव बैंक (All Scheduled Banks) में खाता खुलवाकर धनराशि का वितरण किया जाय। इस प्रकार ये समस्त विकल्प लाभार्थी को उपलब्ध रहेंगे।

4. 10 से 18 वर्ष के बच्चों का स्वयं का खाता या उनके माता-पिता के साथ संयुक्त खाता खोला जा सकेगा। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खाते बैंक के नियमों के अनुसार उनके संरक्षकों (Natural Guardian) के द्वारा संचालित किये जा सकेंगे।

5. जिन प्रकरणों में लाभार्थी द्वारा पहले से या अब तक की कार्यवाही तक पोस्ट आफिस या बैंकों में खाते खोल लिये गये हैं और उन्हें कोई कठिनाई नहीं है तो उन्हें यथावत् स्वीकार कर लिया जाय।

6. नये लाभार्थियों के प्रकरणों में विकल्प के आधार पर पोस्ट आफिस तथा बैंक में खाता खोलना सुनिश्चित किया जाय। पोस्ट आफिस में खाता खोलने हेतु Zero Balance की सुविधा पूर्व से निर्धारित है। कामर्शियल बैंक/ग्रामीण बैंक/को-ऑपरेटिव बैंक में भी लाभार्थियों को नो-फ्रिल्स एकाउन्ट (No-Frills Account) अर्थात् Zero Balance के साथ खाता खोलने की सुविधा प्रदान कर दी गयी है। इसके लिये यह सुनिश्चित किया जाय कि समस्त लाभार्थियों के पेंशन व छात्रवृत्ति के खाते दिनांक 30 सितम्बर, 2008 तक प्रत्येक दशा में सम्बन्धित डाकघरों अथवा बैंकों में खुलवा लिये जायें।

7. ऐसे लाभार्थी जो गम्भीर विकलांगता की श्रेणी में हैं उन्हें उनकी सहमति के आधार पर मनी आर्डर के द्वारा धनराशि का वितरण किया जायेगा। ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जाना आवश्यक होगा।

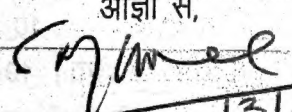
अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की आख्या प्रत्येक तीन माह बाद शासन में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 484/XVII-02/2008-01(33)/2006 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मंडल पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तराखण्ड परिमंडल, देहरादून।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक आफ पटियाला, बी०ओ०बी०, ओ०बी०सी०, केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इलाहाबाद बैंक, यू०बी०आई०, आई०ओ०बी० सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, देना बैंक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, इंडियन बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, विजया बैंक, जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष-उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक।
8. उपमहाप्रबन्धक, पी०एन०बी०, सर्किल कार्यालय ए-1, पल्टन बाजार, देहरादून।
9. मंडलीय प्रबन्धक, यू०को० बैंक, सिंडीकेट बैंक।
10. आंचल प्रबन्धक, बैंक आफ इण्डिया, कार्पोरेशन बैंक।
11. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर भारत क्षेत्र यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया।
12. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. अनुभाग अधिकारी, समाज कल्याण अनुभाग 1 एवं 3, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 15. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्नेहलता अग्रवाल)
अपर सचिव।